भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.03.2026 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3033 का उत्तर

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में लंबित रेल परियोजनाएं

3033. श्री आदित्य यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कई रेल परियोजनाएं लंबित हैं या विलंबित हैं जिससे आवश्यक संपर्क कमजोर और व्यापार प्रभावित हो रहा है तथा जिले की आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो बदायूं जिले के निवासियों और उद्योगों के हित में पर्याप्त बजट आवंटन, ठेकेदारों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने, परियोजना निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और पूर्णता की अवधि में तेजी लाने के लिए इन रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार द्वारा क्या विस्तृत सुधारात्मक कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): बदायूँ की संपर्कता में सुधार के लिए कासगंज - बदायूँ - बरेली जंक्शन का आमान परिवर्तन कार्य पूरा कर लिया गया है।

वर्तमान में, बदायूँ को निम्नलिखित 14 रेल सेवाओं द्वारा सेवित किया जा रहा है जो स्टेशन के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करती हैं:

क्र.सं.	रेलगाड़ी संख्या और नाम
1	15055 आगरा फोर्ट-रामनगर एक्सप्रेस
2	15056 रामनगर-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस

3	15061 कासगंज-लालकुआं जंक्शन एक्सप्रेस
4	15062 लालकुआं जंक्शन -कासगंज एक्सप्रेस
5	22975 बांद्रा (टी) - रामनगर एक्सप्रेस
6	22976 रामनगर-बांद्रा (टी) एक्सप्रेस
7	55307 कासगंज- रामनगर पैसेंजर
8	55308 रामनगर-कासगंज पैसेंजर
9	55311 कासगंज-लालकुआं जंक्शन पैसेंजर
10	55312 लालकुआं जंक्शन - कासगंज पैसेंजर
11	55327 कासगंज-बरेली सिटी पैसेंजर
12	55328 बरेली सिटी-कासगंज पैसेंजर
13	55329 कासगंज-बरेली सिटी पैसेंजर
14	55330 बरेली जंक्शन-कासगंज पैसेंजर

इसके अलावा, किसी भी मार्ग/खंड पर रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करना, जो सतत् प्रक्रिया है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें शामिल हैं:-

- उस खंड की क्षमता
- मार्ग की उपलब्धता
- अपेक्षित चल स्टॉक की उपलब्धता
- चल स्टॉक के लिए संबंधित अवसंरचना की उपलब्धता
- रेलपथ और अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की आवश्यकता

<u>उत्तर प्रदेश</u>

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	19,858 करोड़ रुपए (लगभग 18 गुना)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाले नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 किलोमीटर	199 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-25	5,272 किलोमीटर	479 किलोमीटर प्रतिवर्ष (2 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाली 62,360 करोड़ रुपए लागत पर 3,807 किलोमीटर कुल लंबाई की 49 परियोजनाएं (10 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 37 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च, 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	10	1227	340	10517
आमान परिवर्तन	02	67	0	281
दोहरीकरण/बहुपथन	37	2513	983	19813
कुल	49	3807	1323	30611

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाली तथा हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	डोमिनगढ़-गोरखपुर-कुसुम्ही - तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण (21 किलोमीटर)	508
2	बहराइच-नानपारा-नेपाल गंज आमान परिवर्तन (56 किलोमीटर)	342
3	बलिया-गाजीपुर सिटी दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	650
4	गाज़ीपुर सिटी-तारीघाट नई लाइन (17 किलोमीटर)	1766

5	गोंडा-गोरखपुर लूप आमान परिवर्तन (260 किलोमीटर)	863
6	गोंडा-बहराइच आमान परिवर्तन (60 किलोमीटर)	318
7	बाराबंकी-अकबरपुर दोहरीकरण (161 किलोमीटर)	1700
8	कप्तानगंज-थावे-छपरा आमान परिवर्तन (234 किलोमीटर)	819
9	पीलीभीत-शाहजहांपुर आमान परिवर्तन (83 किलोमीटर)	589
10	इंदारा-दोहरीघाट आमान परिवर्तन (34 किलोमीटर)	213
11	लखनऊ-पीलीभीत आमान परिवर्तन (263 किलोमीटर)	1634
12	भदोही-जंघई दोहरीकरण (31 किलोमीटर)	168
13	लहोटा-भदोही दोहरीकरण (39 किलोमीटर)	184
14	मेरठ-मुजफ्फरनगर दोहरीकरण (55 किलोमीटर)	430
15	फाफामऊ-प्रयागराज दोहरीकरण (14 किलोमीटर)	212
16	मुजफ्फरनगर-टपरी दोहरीकरण (52 किलोमीटर)	525
17	उतरेटिया-रायबरेली दोहरीकरण (66 किलोमीटर)	662
18	रायबरेली-अमेठी दोहरीकरण (60 किलोमीटर)	668
19	आलमनगर-उतरेटिया दोहरीकरण (20 किलोमीटर)	358
20	भीमसेन-झांसी दोहरीकरण (206 किलोमीटर)	2620
21	इटावा-मैनपुरी नई लाइन (58 किलोमीटर)	313
22	मल्हौर-डालीगंज दोहरीकरण (13 किलोमीटर)	183
23	रूमा चकेरी- चंदारी तीसरी लाइन (13 किलोमीटर)	177
24	बरेली-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन (102 किलोमीटर)	313
25	रोसा-सीतापुर कैंट-बुढ़वल दोहरीकरण (181 किलोमीटर)	2094
26	जौनपुर-अकबरपुर (टांडा) दोहरीकरण (77 किलोमीटर)	676
27	रमना-रेणुकूट-सिंगरौली दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	2436
28	जंघई-फाफामऊ दोहरीकरण (47 किलोमीटर)	414

29	वाराणसी-माधोसिंह-प्रयागराज दोहरीकरण (120 किलोमीटर)	2018
30	करैला रोड- शक्तिनगर दोहरीकरण (32 किलोमीटर)	763
31	देवबंद (मुजफ्फरनगर)-रुड़की (27 किलोमीटर)	1289
32	आगरा-इटावा नई लाइन (110 किलोमीटर)	427
33	फेफना-इन्दारा, मऊ-शाहगंज दोहरीकरण (150 किमी)	1778

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः तौर पर आने वाली कुछ परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	बाराबंकी-बुढ़वल तीसरी लाइन (27 किलोमीटर)	426
2	बुढ़वल- गोंडा कचहरी चौथी लाइन (56 किलोमीटर)	796
3	बुढ़वल-गोंडा तीसरी लाइन (62 किलोमीटर)	1118
4	बहराइच-खलीलाबाद नई लाइन (240 किलोमीटर)	4940
5	कटरा और अयोध्या धाम दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	466
6	पंडित दीन दयाल उपाध्याय- प्रयागराज तीसरी लाइन (150 किलोमीटर)	2649
7	बिल्ली-चुनार दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1424
8	छपरा-बलिया दोहरीकरण (65 किलोमीटर)	1046
9	ऊंचाहार-अमेठी नई लाइन (66 किलोमीटर)	1229
10	एटा-कासगंज नई लाइन (29 किलोमीटर)	389
11	गोरखपुर- वाल्मीकिनगर दोहरीकरण (96 किलोमीटर)	1121
12	वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय तीसरी और चौथी लाइन (15 किलोमीटर)	2464
13	झांसी-खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन दोहरीकरण (431 किलोमीटर)	4330
14	सहजनवा-दोहरीघाट नई लाइन (81 किलोमीटर)	1320

सरकार द्वारा रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर धन के आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि

(iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) परियोजना की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर गहन निगरानी, और (vi) शीघ्रोशीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी एवं वन्यजीव स्वीकृतियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्तन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 से चालू करने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

स्टेशन पुनर्विकास:

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैः-

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान,
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान,
- प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर,
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,

- **प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान।**

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। इनमें से बदायूँ जिले के बदायूँ और उझानी स्टेशन सहित 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जं., बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गाजियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन,

		कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासों रोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उत्तर रेलवे, लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे), मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, मगहर, महाराजा बिजली पासी, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्हौर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मारियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जंक्शन, फूलपुर, पीलीभीत जंक्शन, पोखरायां, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हाल्ट, रामपुर जंक्शन, रेनुकूट, सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जंक्शन, शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर जंक्शन, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जंक्शन, उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जंक्शन, उतरेतिया जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, व्यासनगर, जाफराबाद

उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 23 स्टेशनों (अयोध्या धाम जंक्शन, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर, गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, खलीलाबाद, मैलानी

जंक्शन, पनकी धाम, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी) पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अन्य स्टेशनों पर भी विकास संबंधी गतिविधियां तेज गति से शुरू की गई हैं और उपर्युक्त में से कुछ स्टेशनों की प्रगति नीचे दी गई है:

- बदायूँ स्टेशन: पार्किंग क्षेत्र, शौचालय, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह और प्रतीक्षालय का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन का सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है।
- गाजियाबाद स्टेशन: मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार की ओर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, टुंडला छोर पर नए पैदल पार पुल-बी का नींव संबंधी कार्य, रूफ प्लाजा, मौजूदा पैदल पार पुल-ए का विस्तार कार्य, मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर विद्युत सब-स्टेशन को अंतिम रूप देने का कार्य, मजिस्ट्रेट भवन, राजकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल के भवनों का कार्य शुरु किया गया है।
- रामपुर स्टेशन: नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, शौचालय का कार्य पूरा हो चुका है। परिचलन क्षेत्र और पैदल पार पुल के कार्य शुरू किए गए हैं।
- शाहजहांपुर स्टेशन: प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 / 3 पर प्लेटफॉर्म शेल्टर और सतह के कार्य पूरे हो चुके हैं। स्टेशन भवन का सुधार कार्य, दूसरे प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र और पैदल पार पुल के कार्य शुरू किए गए हैं।
- शिकोहाबाद जंक्शन स्टेशन: नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म संख्या 1 / 2 की सतह का कार्य, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग और दिव्यांगजन सुविधाओं का कार्य पूरा हो चुका है। 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और चलायमान प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के

विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/सम्हाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

भारतीय रेल में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक सुव्यवस्थित स्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता की जाँच तथा लेखापरीक्षा शामिल हैं। निर्माण कार्य विभिन्न संहिताओं एवं नियमावलियों में निर्धारित मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप निष्पादित किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहु-विषयक दलों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुदेशों के अनुसार निरीक्षण/लेखापरीक्षा/जाँच की जाती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाती है। यह सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, विद्युत/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पाँच क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,794 करोड़ रुपए का आबंटन किया

गया है, जिसमें से अब तक (जनवरी, 2026 तक) 3,343 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल:

भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे निर्माण कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण और शुरुआत गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-26 (जनवरी, 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (जनवरी 2026 तक)	14,024 अदद (उत्तर प्रदेश राज्य में 1,702 ऊपरी/निचले सड़क पुल सहित)

01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में कुल 1,14,196 करोड़ रुपए की लागत पर 4802 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश राज्य में 15,170 करोड़ रुपए की लागत से 778 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। जिनमें से 22.86 करोड़ रुपए की लागत पर 5 अदद निचले सड़क पुल बदायूँ जिले में स्वीकृत हैं। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	समपार का ब्यौरा	टिप्पणियां
1.	कासगंज-लालकुआं खंड पर समपार संख्या 270	इस स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य 4.77 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	कासगंज-लालकुआं खंड पर	इस स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य

	समपार संख्या 302	4.84 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	चन्दौसी-हरदुआगंज खंड पर किमी 111/12-13 (गैर समपार स्थान)	इस स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य 3.64 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है। कार्य शुरू कर दिया गया है।
4.	कासगंज-लालकुआं खंड पर समपार संख्या 275	इस स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य 4.77 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है।
5.	कासगंज-लालकुआं खंड पर समपार संख्या 286	इस स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण कार्य 4.84 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत किया गया है।

किसी ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य को पूरा करना, पहुंच मार्ग का संरेखण निर्धारित करने, सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) के अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना विशिष्ट/कार्य स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी/निचले सड़क पुलों कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के हिस्से में स्पैन के विभिन्न संयोजनों, तिर्यकता और सड़क की चौड़ाई हेतु अधिसंरचना आरेखणों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे सर्वत्र रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए त्वरित योजना बनाने हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।

(iv) जहां कहीं संभव हो, ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को रेलवे द्वारा एकल निकाय के आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहती है तो रेलवे उन्हें एकल निकाय के आधार पर कार्य निष्पादित करने की अनुमति दे सकती है।

******